



केरल में भारी बारिश से तबाही, 5 की मौत; 2 लोग लापता

मलप्पुरम(ए)। केरल में मूसलाधार बारिश के बीच भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से अलग-अलग घटनाओं में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग अभी भी लापता हैं। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। अधिकारियों को स्थिति की लगातार समीक्षा करने और संवेदनशील इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। मलप्पुरम जिले के निलंबूर-अमरंबलम इलाके में रविवार शाम कोझुपुझा नदी में अचानक आई बाढ़ में पांच लोग बह गए। बताया गया कि वंडूर का एक समूह नदी में नहाने पहुंचा था। अचानक जलस्तर बढ़ने से सभी पानी के तेज बहाव में बह गए। एक व्यक्ति को स्थानीय निवासी ने बचा लिया, जबकि दो लोगों के शव बरामद किए



गए। दो अन्य अब भी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए विशेष आपदा प्रबंधन टीम तैनात की गई है।

कोट्टायम और इडुक्की में भूस्खलन कोट्टायम जिले के टीकोय के पास वेलाथुसेरी में भूस्खलन की चपेट में

वागामोन से लौट रही थीं। सड़क पर पहाड़ी से खिसकी मिट्टी उनके ऊपर गिर गई। हादसे में उनकी सहेली घायल हुई हैं। इडुक्की के कोट्टाकम्बूर में बारिश से बचने के लिए शेड में रुके तीन लोग भूस्खलन की चपेट में आ गए। पहाड़ी से मिट्टी का बड़ा हिस्सा शेड पर गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हुई।

अगले चार दिन भारी बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने केरल के कुछ हिस्सों में अगले चार दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। 20 और 21 सितंबर को कुछ इलाकों में आंधी-तूफान की भी संभावना है। कोट्टायम और इडुक्की में रविवार को अर्रेंज अलर्ट जारी किया गया। राज्य में 1 जून से 17 सितंबर के बीच सामान्य से 28 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी।

राजनीति ‘अंडा अटैक’ का बढ़ा ट्रेंड: पश्चिम बंगाल से शुरु हुआ सिलसिला पंजाब तक पहुंचा

नई दिल्ली,(ए)। देश की राजनीति में विरोध प्रदर्शन का एक नया और हिंसक स्वरूप तेजी से पैर पसार रहा है। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ नेताओं पर अंडा फेंकने (अंडा अटैक) का सिलसिला अब देश के अन्य राज्यों में भी पहुंच गया है। हाल ही में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के कार्फिले पर हुए अंडा अटैक के बाद राजनीतिक हलकों में बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर गर्म हो गया है।

पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार जाने के बाद से नेताओं पर अंडे से अटैक करने का सिलसिला तेजी से शुरु हुआ था, जिस पर लगातार चर्चाएं भी हो रही थीं। सरकार ने इसे रोकें जाने और उचित कार्रवाई करने का कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया, जिसका अब असर अन्य राज्यों में देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पंजाब में नरेश के खिलाफ निकाली जा रही एक यात्रा के दौरान भाजपा नेताओं और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के कार्फिले पर अंडे और टमाटर फेंके गए। घटना के बाद रवनीत बिट्टू ने मीडिया के सामने अंडे और टमाटर दिखाते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे पंजाब सरकार और स्थानीय पुलिस की शह पर रचा गया प्रायोजित हमला करार दिया।



पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल की सरकार की ही तरह दावा किया है कि यह जनता का स्वाभाविक गुस्सा था, जो नेताओं के प्रति भड़का। इस बीच, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी पंजाब की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जेड-एलएस सुरक्षा प्राप्त नेताओं की गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, तो राज्य में आम नागरिक कितना सुरक्षित होगा

पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था ट्रेंड गौरतलब है कि नेताओं पर सार्वजनिक स्थलों या गाड़ियों पर अंडे फेंकने की घटनाएं सबसे पहले पश्चिम बंगाल में चर्चा में आई थीं। वहां सरकार जाने के बाद तुणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं को अलग-अलग मौकों पर ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल की बैठकों,

रैलियों और कार्फिलों पर अंडे फेंकने की इन घटनाओं को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट तक में सवाल उठाए गए थे।

लोकतंत्र के लिए चिंताजनक ट्रेंड विश्लेषकों का मानना है कि चाहे पश्चिम बंगाल हो या पंजाब, किसी भी राज्य में नेताओं पर इस प्रकार के हमले लोकतंत्र में स्वस्थ विरोध का प्रतीक नहीं हैं। विरोध दर्ज कराने की आड़ में इस तरह के तरीके अपनाना न केवल कानून-व्यवस्था की पोल खोलता है, बल्कि राजनीतिक माहौल को भी खराब करता है। अंडा और टमाटर फेंकने की यह राजनीति अब देश के अन्य राज्यों में भी एक खतरनाक ट्रेंड का रूप लेती दिख रही है, जिस पर सभी राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र के विखे पाटिल परिवार की नीला स्वीडन की संसद पहुंची

स्टॉकहोम सिटी सीट से रिक्सडाय के लिए चुनी गईं, परिवार में खुशी का माहौल

नीला, अशोक विखे की बेटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री बालासाहेब विखे पाटिल की पोती हैं

मुंबई,(ए)। महाराष्ट्र के विखे पाटिल परिवार से ताल्लुक रखने वाली नीला विखे पाटिल स्वीडन की संसद रिक्सडाय के लिए चुनी गई हैं। 13 सितंबर को हुए स्वीडन के राष्ट्रीय चुनाव में उन्होंने स्टॉकहोम सिटी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। स्वीडन की संसद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नीला विखे पाटिल को ग्रीन पार्टी की सदस्य और स्टॉकहोम सिटी निर्वाचन क्षेत्र की सांसद के रूप में दर्ज किया गया है। इससे महाराष्ट्र में उनके परिवजनों में खुशी का माहौल है। यहां बताते चलें कि नीला महाराष्ट्र के शिक्षाविद अशोक



विखे पाटिल की बेटी, पूर्व केंद्रीय मंत्री बालासाहेब विखे पाटिल की पोती और महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की भतीजी हैं। उनका जन्म स्वीडन में हुआ, लेकिन बचपन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीता। नीला लंबे समय से स्वीडन की राजनीति में सक्रिय रही हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवैन के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया। इस

दौरान उन्होंने वित्त, कराधान और आवास जैसे विषयों पर काम किया। वह स्टॉकहोम नगर परिषद में भी सदस्य रह चुकी हैं।उनकी शिक्षा स्वीडन और स्पेन में हुई है। उन्होंने गोथेनबर्ग स्कूल ऑफ बिजनेस से स्नातक और एमबीए की पढ़ाई की तथा मैड्रिड की कॉम्प्लूटेंस यूनिवर्सिटी में भी अध्ययन किया। 2020 से वह पीडब्ल्यूसी से जुड़ी हैं और अप्रैल 2025 में आधिकारिक पब्लिक अकाउंटेंट बनीं।

उत्तराखंड में कलह: मंत्री खजानदास ने दे डाली सुसाइड की धमकी

देहरादून(ए)। उत्तराखंड में भाजपा के भीतर का घमासान अब खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले चकराता क्षेत्र में अनदेखी से नाराज भाजपाइयों ने अपनी ही सरकार के एक मंत्री के आवास का घेराव किया। अपनों के लगाए गंभीर आरोपों से आहत होकर मंत्री खजानदास ने दो टुक कहा कि यदि उन पर लगे आरोप साबित हुए तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और आत्महत्या कर लेंगे।

रिविवार को यमुना कॉलोनी स्थित मंत्री आवास पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में यह आम चर्चा है कि 15 से 20 प्रतिशत कमीशन देकर विपक्षियों ने अपनी योजनाएं मंजूर कराई हैं। इससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। उनका दावा है कि कथित तौर पर कांग्रेस के लोगों को 80 प्रतिशत तक काम दिया गया, जबकि चुनावी वर्ष में भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रस्तावों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री खजानदास पर जानबूझकर चकराता में भाजपा को कमजोर करने का आरोप लगाया।

इन आरोपों की तपिश से मंत्री खजानदास ने मीडिया से कहा कि 95 ब्लॉक में संतुलित विकास उनकी प्राथमिकता है। समाज कल्याण से जुड़ी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की योजनाओं के साथ ही स्पेशल कम्पैनेंट प्लान (एससीपी) का बजट पूरे राज्य में बिना भेदभाव दिया गया। उन्होंने दावा किया कि चकराता को सबसे ज्यादा बजट मिला है और संतुलन बनाना जरूरी है, पर कुछ लोग सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मंत्री और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद भाजपाइयों ने सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलने और चकराता के प्रकरण को उनके समक्ष रखने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष से भी इस संबंध में बात की गई है। देहरादून की चकराता विधानसभा सीट दशकों से कांग्रेस का मजबूत किला रही है, जहां वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह विधायक हैं। इस दुर्ग को भेदने में जुटी भाजपा के लिए यह अंदरूनी कवाह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। धरने की अगुवाई कर रही मधु चौहान खुद चकराता से चुनाव लड़ चुकी हैं और उनके पति विकासनगर से भाजपा विधायक हैं। उन्होंने बताया कि बजट वितरण में विपक्षी दलों के समर्थकों को तर्जवीह दिए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान लगे कथित नारों और तीखे बयानों ने सरकार से लेकर संगठन तक को असहज कर दिया है। चुनावी बेला से पहले अपने ही कार्यकर्ताओं की ओर से मंत्री पर आरोप लगाने से पार्टी असहज है और आलाकमान ‘डैमेज कंट्रोल’ की कवायद में जुट गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपाई मानते हैं या पार्टी संगठन कोई ठोस कदम उठाएगा।

गंगा नदी में डूबने से 6 बच्चों की मौत

भागलपुर(ए)। बिहार के भागलपुर में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां कर्म-धर्मा पूजा के अवसर पर स्नान करने गए छह बच्चों की बाढ़ के पानी में डूबकर मौत हो गई। यह दुखद हादसा सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 स्थित विष्णु टोला के पास तरैया नारायणपुर बस्तिार में हुआ। इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया है और पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार, सभी बच्चे करीब 12 वर्ष की आयु के थे। कर्मा-धर्मा पूजा के महेनजर ये बच्चे बाढ़ के पानी में स्नान करने गए थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चों की तलाश शुरू की। काफी प्रयासों के बाद सभी बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। मृत बच्चों की पहचान पूजा, ज्योति, मिंकी, राहुल, आयुष और विकास के रूप में हुई है। ये सभी सुल्तानगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 27 स्थित विष्णु टोला के निवासी बताए जा रहे हैं। एक साथ छह बच्चों की मौत की खबर मिलते ही मृत बच्चों के परिवारों में कोहराम मच गया। पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है, और परिजनों को संभालना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, इलाके में पहले से ही बाढ़ का पानी भरा हुआ था। बच्चों का गहरे पानी में चले जाना ही इस दर्दनाक हादसे का कारण बना। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसे जलभराव वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और बच्चों को बाढ़ के पानी से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि बाढ़ के दौरान विशेष निगरानी जरूरी है ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। प्रशासन की ओर से घटना की जानकारी जुटाई जा रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

पेवल नदी दी तो हाईकोर्ट ने रोक दी अधिकारियों को सैलरी

चंडीगढ़(ए)। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में चार सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। यह कदम एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनकी पत्नी की पेंशन के लिए 2007 से कार्यालयों के चक्कर कटवाने के आरोप में उठाया गया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट की अनुमति के बिना इन कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा कि जब तक संबंधित कर्मचारी मिलकर याचिकाकर्ता की पेंशन और एरियर का मुद्दा नहीं सुलझाते, तब तक किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगी। याचिकाकर्ता जगदीश राज ओरोड़ा ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया था कि उनकी पत्नी, जो गुरदासपुर में ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर थी, की पेंशन और एरियर उन्हें 2007 से अब तक नहीं मिला है।

फरक्का जल संधि का मियाद हो रही खत्म, बिहार में संधि का हो रहा विरोध

पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश को भी जल का मुद्दा पड़ सकता भारी

नई दिल्ली,(ए)। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश को भी जल का मुद्दा भारी पड़ सकता है। इस साल के अखिर में पूरी हो रही फरक्का जल संधि को भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा सकता है। दरअसल, भारत की नीति पड़ोसी देशों के साथ समन्वय की रही है, लेकिन कई देशों की राजनीति ने अक्सर भारत के लिए दिक्कतें खड़ी की हैं। इनमें बांग्लादेश भी शामिल है, जिसने कई मुद्दों पर टकराव की स्थिति पैदा की है।

बता दें ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। इसके बाद से पाक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुहार लगा रहा है। वहीं, अब बांग्लादेश का भारत के प्रति रुख रक्षात्मक है। इसकी वजह फरक्का जल संधि है। गंगा पर भारत, बांग्लादेश के बीच यह संधि बेहद खास है। संधि पर 12 दिसंबर 1996 को हस्ताक्षर हुए थे, जो एक जनवरी से 31 मई के दौरान फरक्का बैराज से गंगाजल का वितरण तय करती है। यह संधि दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है। अब भारत पर निर्भर है कि वह इसे कैसे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बिहार में इस संधि का विरोध हो रहा है।



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार और बीजेपी की सहयोगी जेडीयू का तर्क है कि फरक्का बैराज की वजह से गंगा में गाद जमा हो गई है, जिससे नदी का तल ऊंचा हो गया है। इससे मानसून में बिहार में बाढ़ का खतरा रहता है। गर्मियों में जलस्तर घटने से जल की कमी का सामना करना पड़ता है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कहना है कि संधि खत्म होने के बाद बिहार समेत गंगा बेसिन के राज्यों की 2050 तक की जल की जरूरतों का आकलन कर नई व्यवस्था बनाई जाए। संसद के मानसून सत्र में यह मुद्दा उठा था। तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सरकार बिहार की जरूरतों-चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सही फैसला लेगी। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद

ने कहा कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार पिछले कई सालों से गाद प्रबंधन, फरक्का बराज, गंगा की अखिरलता और बिहार के जल अधिकारों का मुद्दा उठाते रहे हैं। वहीं संजय कुमार झा की ओर से हाल में राज्यसभा में फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के विरोध में दिए गए बयान के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गंगा में गाद के जमाव को बिहार में बाढ़ की गंभीर समस्या के प्रमुख कारणों में एक मानते रहे हैं। गाद के कारण नदी की जलधारण क्षमता और प्रवाह की गहराई घटती है, जिससे अधिक पानी आने पर नदी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। गाद प्रबंधन की समस्या का समाधान किए बिना नर्नामि गंगे जैसी योजनाओं का उद्देश्य पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता।

राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्रा शुरु करेंगे प्रशासनिक कामकाज

अयोध्या,(ए)। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव होने वाला है। नए नियुक्त किए गए सीईओ एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) सोमवार को मंदिर के कामकाज का पूरा चार्ज संभालेंगे। जितेंद्र मिश्रा मंदिर के प्रशासनिक कामकाज की देखरेख शुरू करेंगे। ऐसे में उनके राम मंदिर परिसर और अयोध्या में ही रहने की उम्मीद है। इससे मंदिर के व्यवस्थाओं की निगरानी आसान और प्रभावशील होगी। नए सीईओ की नियुक्ति राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बाद हुई है। ट्रस्ट ने प्रशासनिक देखरेख को मजबूत करने और मंदिर से जुड़ी गतिविधियों के बेहतर मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने के लिए मिश्रा को नियुक्त किया है। उनके पूरा चार्ज संभालने से मंदिर परिसर के कामकाज में बदलाव आने की उमीद है। चढ़ावे के मैनेजमेंट, सुरक्षा इंतजामों और रोजाना के प्रशासनिक कामकाज पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की संभावना है। राम मंदिर में बढ़ती भीड़ को मैनेज करना, सुविधाओं को बनाए रखना और भक्तों के चढ़ावे को संभालने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना मंदिर प्रशासन के अहम पहलू हैं।मीडिया रिपोर्ट के मुताबक मिश्रा के अयोध्या में रहने और मंदिर परिसर में उपलब्ध रहने के फैसले से रोजाना की गतिविधियों की बेहतर निगरानी हो सकेगी। उनकी मौजूदगी से मंदिर मैनेजमेंट के अलग-अलग पहलुओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के बीच तेजी से तालमेल बिठाना भी आसान हो सकता है। सीईओ नियुक्त करने का ट्रस्ट का फैसला अहम है क्योंकि मंदिर प्रशासन को चढ़ावे को संभालने को लेकर चिंताओं के बीच लोगों का भरोसा बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भक्त और आने वाले लोग मंदिर के प्रशासनिक कामकाज में बदलाव देख सकते हैं। हालांकि, नई व्यवस्थाओं, कामकाज में बदलाव और गड़बड़ियों को रोकने के उपायों के बारे में खास जानकारी अभी तक नहीं दी गई है।



पाकिस्तान ने दबाव में किया है अजहर को एफआईए की रेड बुक में भगोड़ा घोषित

भारत बोला- आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई घोषणाओं से नहीं, ठोस कदमों से साबित होती है

नई दिल्ली,(ए)। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की अक्टूबर में होने वाली बैठक से पहले पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर घोषित इनाम बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए कर दिया है। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसे 2026 की मोस्ट वांटेड सूची में भगोड़े के तौर पर शामिल किया है। एफएटीएफ की अगली प्लेनरी बैठक 26 से 30 अक्टूबर तक पेरिस में होना है। रिपोर्टों के मुताबिक मसूद अजहर पर पहले 50 लाख पाकिस्तानी रुपए का इनाम घोषित था, जिसे अब बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दिया गया है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब पाकिस्तान की आतंकवाद और आतंकी वित्तपोषण से निपटने की व्यवस्था पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर से निगाह है। पाकिस्तान अक्टूबर

2022 में एफएटीएफ की बड़ी हुई निगरानी वाली सूची से बाहर हुआ था। भारत ने पाकिस्तान के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे महज



दिखावटी कदम बताया है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस कदमों से साबित होती है। बता दें मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक और प्रमुख हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मई 2019 में उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। भारत में उस पर संसद हमले समेत

कई आतंकी मामलों में वांछित होने का आरोप है। 1999 में कंधार विमान अपहरण के दौरान भारतीय जेल से रिहा किए जाने के बाद उसने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की थी। पाकिस्तान लंबे समय से दावा करता रहा है कि मसूद अजहर देश में नहीं है और अफगानिस्तान चला गया है। हालांकि, उसके ठिकाने को लेकर भारत और पाकिस्तान के दावों में अंतर रहा है। एफएटीएफ की 26 से 30 अक्टूबर तक होने वाली प्लेनरी बैठक में सदस्य देश आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों पर चर्चा करेंगे। ऐसे में मसूद अजहर को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल करने और उस पर इनाम बढ़ाने के पाकिस्तान के फैसले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी कार्रवाई के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस कदम का एफएटीएफ के अगामी फैसले पर क्या असर पड़ेगा यह बैठक में होने वाली समीक्षा पर निर्भर होगा।

